इकाई 7 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और महत्त्व

संरचना

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 कृषि की भूमिका : सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

7.3 कृषि और गैर-कृषि सेक्टरों के बीच परस्पर संबद्धता

7.4 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व
- 7.4.1 सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान
- 7.4.2 रोज़गार में योगदान
- 7.4.3 निर्यात में योगदान
- 7.4.4 गरीबी न्यूनीकरण में भूमिका
- 7.4.5 खाद्य और पौषणिक सुरक्षा में भूमिका
- 7.4.6 समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने में योगदान
- 7.4.7 आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा-जाल में भूमिका
- 7.4.8 ऊर्जा सुरक्षा में भूमिका
- 7.4.9 पारितंत्र सेवाओं में योगदान

7.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की बदलती हुई भूमिका

7.6 रोजगार/GDP अंतरण और रोजगार नम्यता

7.7 सारांश

7.8 शब्दावली

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- कृषि की बदलती हुई (अर्थात् परंपरागत और आधुनिक या धारणीय और वाणिज्यिक) भूमिका के बीच अंतर कर सकेंगे, और इस दृष्टि से समसामयिक काल के लिए उसका नवीकृत महत्त्व बता सकेंगे;
- आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कर सकेंगे;
- कृषि और गैर-कृषि सेक्टरों के बीच अंतर संबद्धता समझा सकेंगे;
- भारतीय अर्थव्यवस्था को उसके बहुपक्षीय परिप्रेक्ष्य में कृषि के महत्त्व की चर्चा कर सकेंगे;

- वर्तमान आर्थिक वितरण में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की बदलती हुई भूमिका बता सकेंगे; और
- कृषि और गैर-कृषि सेक्टरों के बीच रोज़गार अंतरण/नम्यता में प्रवृत्तियों के महत्त्व पर प्रकाश डाल सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

भारतीय कृषि में नव-उदार नीति शासन प्रणाली के दो दशकों के दौरान महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। ग्रामीण आजीविका के अनुसार कृषि अभी भी देश की कुल श्रमशक्ति से आधे से भी अधिक को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान कर रही है। परंतु कुल GDP में योगदान के आधार पर यह एक अवशिष्ट सेक्टर होकर रह गया है। ये 1951 में 52.2 प्रतिशत के उच्च स्तर की तुलना में इस समय 15 प्रतिशत से भी कम हो गया है। स्पष्टतः संवृद्धि पथ गैर-कृषि सेक्टर की ओर बहुत सीमा तक चला गया है, फिर भी, कृषि से श्रमशक्ति की अन्यत्र क्षेत्रों की ओर गतिशीलता काफी नहीं है। इसके प्रमुख कारण हैं : (i) आजीविका विविधता विकल्पों की अपर्याप्त उपलब्धता; और (ii) कृषि श्रमिक बल के बहुत बड़े भाग में शिक्षा और कुशलता के अपेक्षित स्तर का अभाव। इस परिदृश्य में अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को केवल औद्योगिक विकास के लिए कारक संसाधनों की निष्कृति की प्रक्रिया के रूप में नहीं सोचा जा सकता, जैसा कि 1950 के और 1960 के दशकों के द्विविध वृद्धि प्रतिमानों द्वारा कल्पना की गई थी। बल्कि, इसे बृहतर सामाजिक आर्थिक महत्त्व के अनुसार देखा जाना चाहिए : जैसे (i) ग्रामीण आजीविका का संरक्षण, (ii) ग्रामीण गरीबी का न्यूनीकरण, (iii) समावेशी वृद्धि के लिए नीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता पर नीति निर्माताओं को सचेत करना; (iv) आर्थिक स्थिरता बनाए रखना; (v) खाद्य और पौषणिक सुरक्षाएँ प्रदान करना; (vi) पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना आदि। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में वर्तमान संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ''कृषि की भूमिका और महत्त्व'' पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रक्रिया में आप अर्थव्यवस्था और उन अंतर्भूत संबद्धताओं में संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो फार्म और गैर-फार्म सेक्टरों के बीच कालांतर में विकसित हुई हैं। इस क्षेत्र में हाल ही के परिवर्तनों के संदर्भ में कृषि की सामाजिक भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

7.2 कृषि की भूमिका : सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

आर्थिक विकास के संदर्भ में कृषि का महत्त्व काफी समय पहले से स्वीकार किया गया है। भू-अर्थशास्त्रियों ने केवल अर्थव्यवस्था के सेक्टर के रूप में कृषि की प्रशंसा की जिससे श्रम और नियोजित पूँजी की आवश्यकताओं से अधिक अधिशेष उत्पादित होता था। क्लासिकल और नवक्लासिकल दोनों धाराओं के अर्थशास्त्रियों ने कृषि की भूमिका प्रमुख मानी है। महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक और अनुभवजन्य साहित्य की रचना की प्रक्रिया में योगदान करने वाले विकास अर्थशास्त्रियों का काफी अधिक ध्यान इसने आकर्षित किया है। इसमें अधिकांश साहित्य अर्थव्यवस्था के परंपरागत कृषि से आधुनिक औद्योगिक स्वरूप में संरचनात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। द्वैधाभासी अर्थव्यवस्था मॉडल मुख्यतया सिंगर, नर्कसे, लेविस, रेनिस और फॉई (जिनमें से कुछ का अध्ययन हमने पहले की इकाई में किया है परंतु यहाँ हम उन्हें पुनः दोहराएंगे,

क्योंकि कुछ अन्य सिद्धांतवादियों के योगदान के अतिरिक्त वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य से उनके बारे में अध्ययन करेंगे) आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए अच्छा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये मॉडल और उन पर आधारित अनुवर्ती अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कृषि अपेक्षाकृत श्रम प्रधान कार्य है जो दुर्लभ पूँजी संसाधनों का पूरा लाभ उठाती है। यह खाद्यान्न, कृषि आधारित और अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल, श्रम, बचत प्रदान कर और गैर-कृषि सामान के लिए माँग उत्पन्न कर आर्थिक विकास में योगदान करती है। इसलिए ये योगदान पर्याप्त रूप में स्पष्ट करते हैं कि अपने ऑफ फार्म (off farm) और ऑन फार्म (on farm) दोनों के विकास में योगदान के कारण समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि विकास महत्त्वपूर्ण है। संभावित अधिशेष श्रम के (नर्कस और रेनिस तथा फाई द्वारा दिए गए) अनुमान अत्यधिक घनी आबादी वाले देशों में 25-40 प्रतिशत है। इस पहलू पर थर्लवाल द्वारा विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था, जब उसने कहा कि पश्चिमी यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का वित्त पोषण काफी सीमा तक कृषि में उत्पादित अधिशेष ने किया था।

लेविस मॉडल कृषि (परंपरागत सेक्टर) में अधिशेष श्रम को विकासशील देशों में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी संभावना के रूप में मानता है। इन देशों में कृषि श्रम की सीमांत उत्पादकता (MP) या तो बहुत कम थी, या नगण्य थी। अतः श्रमिक बल की काफी मात्रा निकालने पर भी कृषि उत्पादन कम नहीं होगा, बल्कि उपयोगी तरीके से आधुनिक सेक्टर में नियोजित किया जा सकेगा। उसका दावा था कि कृषि नियत प्रौद्योगिकी की दशाओं के अधीन भूमि और श्रम का उपयोग करती है और इसलिए श्रमिकों को दी गई मज़दूरी उसके सीमांत उत्पादकता से नीचे होती है। दूसरी ओर, उद्योगों में भूमि उस सीमा तक प्रयुक्त की जाती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मज़दूरी दर के बराबर है। परिणामस्वरूप कृषि से अधिशेष श्रमिक उद्योगों में जाते हैं। एक बार जब कृषि से अधिशेष श्रम हटाया जाता है और कृषि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता औद्योगिक सेक्टर में सीमांत उत्पादकता के बराबर स्तर तक पहुंचती है, तो परंपरागत सेक्टर अपना ''अधिशेष श्रम'' स्वरूप खो देता है और यथासमय में वाणिज्यिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार लुई मॉडल आर्थिक विकास की परिकल्पना को परंपरागत ''न्यून लाभ कृषि सेक्टर'' से ''उच्चतम आधुनिक औद्योगिक सेक्टर' में अधिशेष श्रम की अपेक्षित स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में मानता है। साधारणतया यह द्वैधाभासी मॉडल कृषि को विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पिछड़ा और कम उत्पादनकारी जीवन निर्वाह सेक्टर के रूप में देखता है जिसमें से श्रम और अन्य संसाधन गतिशील/उत्पादनकारी औद्योगिक सेक्टर का विकास बढ़ाने के लिए लिये जा सकते हैं।

उद्योगों के लिए अधिशेष श्रम छोड़ने में कृषि की भूमिका के अलावा, क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने में खाद्य आपूर्तियों की भूमिका पर भी विचार किया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि खाद्य उत्पादन स्थिर रहता है तो उद्योगों में कामगार खाद्यान्न की कमी का सामना कर सकते हैं। इसका परिणाम खाद्य कीमतें बढ़ेगी और परिणामस्वरूप उद्योगों में मज़दूरी में बढ़ोत्तरी होगी। बढ़ती हुई मज़दूरी दरें औद्योगिक संवृद्धि रोकती है (विशेषकर विकास की प्रारंभिक अवस्था के दौरान जब प्रौद्योगिकीय सामान्य तथा श्रमिक प्रधान होती है)। संक्षेप में, इसलिए द्वैधाभासी प्रतिमानों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिकीकरण की गति निर्धारण में कृषि की भूमिका मुख्य रूप में स्वीकार की।

योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास

जॉनसन और मेल्लोर (1961) ने राय व्यक्त की कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कृषि सृजित करती है : (i) निर्यात अर्जन द्वारा पूँजी, (ii) गैर-कृषि सेक्टरों के उत्पादित सामान की खपत के लिए घरेलू माँग; और (iii) बढ़ती हुई आबादी और आय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक अपने ही उत्पादन के लिए अतिरिक्त माँग। इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए कृषि के पाँच योगदानों पर विचार किया। जैसे (i) घरेलू खपत के लिए खाद्य प्रदान करना, (ii) उद्योगों के लिए श्रमिक छोड़ना, (iii) घरेलू औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार का विस्तार करना, (iv) घरेलू बचत की दर बढ़ाना, और (v) कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा आय पैदा करना। कुजनेट्स ने आर्थिक विकास के लिए कृषि के तीन योगदानों की पहचान कर वैकल्पिक शब्दों में वैसा ही कहा, जैसे उत्पाद, बाजार और कारक योगदान। उसके अपने शब्दों में ''यदि कृषि बढ़ती है, यह उत्पादन योगदान करती है, यदि यह अन्य से व्यापार करती है, यह बाजार योगदान करती है, यदि यह अन्य सेक्टरों को संसाधन हस्तांतरण करती है, तो यह कारक योगदान करती है।''

श्यूल्ज ने अपनी पुस्तक 'ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर' में तर्क दिए हैं कि कृषि नई प्रौद्योगिकी अपनाकर न केवल उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम है बल्कि गुणक प्रभावों से अन्य सेक्टरों में भी संवृद्धि बढ़ाने की संभावना रखती है। उसने व्यापक रूप से स्वीकृत तर्क का विरोध किया कि विकासशील देशों में किसान परंपरा या संस्कृति द्वारा नियंत्रित होते हैं और आर्थिक प्रोत्साहनों की अनुक्रिया नहीं करते। उसकी प्रसिद्ध ''दक्ष परंतु गरीब'' परिकल्पना का आशय था कि विकासशील देशों की कृषि में निम्न आय स्तर उत्पादन के उपलब्ध कारकों को निम्न उत्पादकता का परिणाम है और उनके अदक्ष आबंटन के कारण नहीं है। इसलिए कृषि का आधुनिकीकरण इस दुर्बलता को समाप्त करेगा। भारत में हरित क्रांति इसका जीवंत उदाहरण है।

इस प्रकार, पिछले साहित्य में फोकस मुख्य रूप से कृषि की परंपरागत भूमिका पर आग्रह था। परंतु कृषि के ''बहुमुखी स्वरूप'' की स्वीकृति बढ़ रही है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जल संसाधन, जैव विविधता, ग्रामीण गरीबी, खाद्य/ईंधन/ आजीविका/सुरक्षा आदि से संबंधित वर्तमान मुद्दों ने बहुत से विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समग्र विकास एजेंडा में कृषि को एक बार फिर रखा है। विश्व विकास रिपोर्ट (WDR), 2008 ने विकाशील देशों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और संवृद्धि के प्रभावशाली इंजन के रूप में कृषि के महत्त्व को स्वीकारा है। रिपोर्ट कहती है ''कृषि सेक्टर में मंदतर वृद्धि, तेज़ी से बढ़ता गैर-कृषि सेक्टर और श्रम कुशलताओं द्वारा दृढ़ता से विभक्त श्रम बाजार ने ग्रामीण-शहरी-आय अंतर को अधिक चौड़ा किया है, इससे कृषि और ग्राम विकास में निवेश करने के लिए राजनीतिक दबाव और अधिक हुआ है।'' रिपोर्ट चार नीतिगत उद्देश्यों पर फोकस करती है : (i) उच्च मूल्य उत्पादकों के लिए छोटी खेती का विविधीकरण; (ii) प्रौद्योगिकी प्रगति से पिछड़े क्षेत्रों के लिए खाद्य माल में हरित क्रांति का विस्तार; (iii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण में सहायता करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास; और (iv) ग्रामीण गैर-कृषिक अर्थव्यवस्था का संवर्धन।

बोध प्रश्न 1

नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) सामाजिक-आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए (वर्तमान समय में भी) कृषि के सतत् महत्त्व के लिए क्या कारण प्रस्तुत किए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

2) कुजनेट्स द्वारा सुझाए गए अर्थव्यवस्था के लिए कृषि के तीन योगदान बताइए।

.....

.....

.....

.....

3) कृषि की तुलना में गैर-कृषि सेक्टर की संवृद्धि की तीव्र गति का अनुसरण करते हुए बढ़ता हुआ ग्रामीण-शहरी अंतर कम करने के लिए नुस्खे के रूप में WDR 2008 द्वारा क्या चार नीतिगत उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

7.3 कृषि और गैर-कृषि सेक्टरों के बीच परस्पर संबद्धता

कृषि गैर-फार्म क्षेत्र से संबद्धता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में परंपरागत कृषि समग्र ग्राम अर्थव्यवस्था का आधार थी। ग्रामीण कारीगरों, लोहारों, बढ़इयों, बुनकरों, धोबियों, दर्जियों, कुम्हारों, सफाई वालों, नाइयों, आदि की अजीविका प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी (इसे जजमानी प्रथा कहा जाता था)। परंतु जैसे-जैसे कृषि का विकास होता गया वह अधिक बाजारोन्मुखी बनती गई। धीरे-धीरे परंपरागत प्रथा का स्थान 'निवेश-निर्गम बाजार प्रथा'' नाम की नई प्रथा ने ले लिया। कृषि ने प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक और मशीनों सहित बाहरी निवेश पर अधिक निर्भर रहना प्रारंभ किया और इस प्रकार वह कृषि प्रसंस्करण उद्योगों (एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज) के लिए बिक्री योग्य अधिशेष उत्पन्न करने लगी तथा बढ़ती हुई शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में (जैसे सड़क, संचार, बिजली, बैंक, स्कूल, बाजार, सहकारी संस्थाएँ) आधारभूत सुविधा के विकास से और परिणामस्वरूप ग्रामीण शहरी संबद्धता की स्थापना, निवेश, निर्गम और औद्योगिक उपभोक्ता सामान में व्यापार और वाणिज्य बहुत आसान हुआ। फार्म-गैर-फार्म और शहरी-ग्रामीण संबद्धता की इस प्रक्रिया में कृषि चालक के रूप में और ग्रामीण आधारभूत संरचना समर्थक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार हरित क्रांति का अनुसरण करते हुए कृषि संवृद्धि की संबद्धता ने भारत

में कृषि उद्योगों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए फार्म-गैर-फार्म संबद्धता को भी उत्पादन और उपभोग संबद्धता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पादन संबद्धता को आगे अग्र अनुबंधन (कृषि संसाधन कार्य) और पश्चानुबंधन संबद्धता (कृषि को निवेश आपूर्ति) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि की अग्रोन्मुखी उत्पादन संबद्धता कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करता है (जैसे गन्ना, तिलहन, कपास और जूट रेशे, चाय और रबड़, खाद्यान्न, बागवानी और पशुधन)। अभी हाल ही में, कृषि वानिकी भी महत्त्वपूर्ण कृषि कार्यों में से एक हो गई है, जिस पर कागज और प्लाईवुड उद्योग निर्भर है। कृषि वृद्धि पश्चानुबंधन के माध्यम से कृषि आदान आपूर्तिकर्ता उद्योगों को भी प्रोत्साहन देता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कृषि में बाह्य आदानों के भाग (खरीदे गए निवेशों) में वृद्धि कृषि विकास में वृद्धि के साथ बढ़ती है। निर्वाह कृषि अधिकांशतः आंतरिक आदानों पर निर्भर रहती है, जैसे अपने ही फार्म में उगाए गए बीज, फार्म उत्पन्न खाद, परिवार का श्रम और पशुबल, जबकि आधुनिक कृषि बाह्य आदानों पर अधिक निर्भर करती है, जैसे प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फार्म मशीन, बैंक ऋण, बीमा आदि। बाह्य आदान की आपूर्ति आदान व्यापारियों के माध्यम से उद्योगों द्वारा की जाती है। आदान व्यापारी भी कभी-कभी किसानों को विस्तार सेवाएँ प्रदान करते हैं। उद्योगों से कृषि का पश्चानुबंधन अर्थव्यवस्था में अधिक आय और रोज़गार पैदा करने में सहायता करता है। इस प्रकार, कृषि की वृद्धि गैर-फार्म सेक्टरों से अग्रानुबंधन और पश्चानुबंधन स्थापित करके आर्थिक विकास को महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

कृषि का शेष अर्थव्यवस्था से खपत अनुबंधन भी है। यह गैर-फार्म सेक्टर में बढ़ती हुई श्रमिक बल के उपयोग आवश्यकताएँ भी पूरी करने के लिए खाद्यान्न, फल और सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति करता है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि गैर-फार्म कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों को सस्ते खाद्य की आपूर्ति करते हुए वहां वास्तविक मजदूरी को कम रखना संभव बनाती है। वह इस प्रकार गैर-फार्म सेक्टरों में लाभ और निवेश बढ़ाता है।

उपभोग सहबंधन (या अंतिम भाग प्रमुख) फार्म परिवारों द्वारा गैर-फार्म माल और सेवाओं के लिए बढ़ती हुई माँग से भी उत्पन्न होता है। कृषि आय में वृद्धि से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे टी.वी., फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोटर साइकिल, कार, मोबाइल फोन) सहित विनिर्मित उत्पादों की माँग बढ़ती है। फार्म परिवारों द्वारा विभिन्न सेवाओं का उपभोग भी कृषि विकास के साथ-साथ बढ़ता है। इसके अलावा मांग पक्ष पर उद्योग से कृषि अनुबंधन भी फार्म आय बढ़ाने में उत्प्रेरक कारक के रूप में कार्य करता है। स्थानीय बाजारों में विभिन्न विनिर्मित माल की उपलब्धता, इन सामग्रियों को खरीदने के लिए फार्म और गैर-फार्म आय बढ़ाने में ग्रामीण लोगों को अभिप्रेरक के रूप में कार्य करती है। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण आय में वृद्धि और बेहतर परिवहन और संचार सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित माल के बाजार को बढ़ावा देती है।

7.4 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व

पूर्ववर्ती भागों में हमने आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका और गैर-कृषि (कृषीतर) सेक्टरों से कृषि वृद्धि संबद्धता के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया है। इस भाग में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व के बारे में पढ़ेंगे। कृषि की भूमिका को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक विकास

में कृषि की प्रत्यक्ष भूमिका का आकलन सकल घरेलू उत्पाद (GDP), रोजगार, निर्यात, कृषि-खाद्य उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति और पूँजी निर्माण के लिए बचतों में उसके योगदान के आधार पर किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष भूमिका का आकलन गरीबी-न्यूनीकरण, खाद्य और पौषाणिक सुरक्षा, आर्थिक-स्थिरता, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दों का संतुलन, ग्रामीण गैर-फार्म आय और रोज़गार वृद्धि आदि के आधार पर किया जा सकता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, द्विविध आर्थिक ढाँचे में कृषि को औद्योगिक विकास के लिए कारक संसाधन देने के स्रोत के रूप में देखा गया था, कृषि को निम्न उत्पादनकारी परंपरागत सेक्टर के रूप में जाना गया था। इसलिए इसे आर्थिक विकास में बराबर के भागीदार के रूप में नहीं समझा गया था। परंतु 1960 के और 1970 के दशकों के दौरान प्रौद्योगिकी में नए आविष्कारों और कृषि के लिए नीतिगत सहायता के कारण अग्रानुबंधन और पश्चानुबंधन तरीकों से उसकी गतिशील भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख रही है। इस प्रकार, यद्यपि, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में वृद्धि से GDP में कृषि का योगदान धीरे-धीरे घटा है, अर्थव्यवस्था में इसका विस्तरित योगदान पर्याप्त है। अधिक व्यापक स्तर पर कृषि अर्थव्यवस्था में मूल कृषि उत्पादन प्रणाली (फसल उत्पादन, पशुधन, कृषि वानिकी आदि) और कृषि खाद्य प्रणाली (अर्थात् कृषि उत्पादों का संसाधन, विपणन, वितरण) सम्मिलित हैं। यदि दोनों प्रणालियों के योगदान को साथ मिलाकर विचार करें तो कृषि की भूमिका उससे बहुत उच्चतर सिद्ध होती है जो देश के राष्ट्रीय आय लेखा आँकड़ों में सकल कृषि घरेलू उत्पाद (GDP) के भाग के रूप में अनुमानित की गई है।

7.4.1 सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान

ऐतिहासिक साक्ष्य और अनुभवजन्य अध्ययन दिखाते हैं कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि ने GDP में योगदान काफी किया है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और अधिक औद्योगिक हो जाती है, GDP में फार्म सेक्टर का अंश धीरे-धीरे सिकुड़ने लगता है और गैर-फार्म सेक्टरों का शेयर बढ़ने लगता है, परंतु समग्र GDP में कृषि के घटते हुए शेयर का अभिप्राय यह नहीं है कि कृषि प्रगति नहीं कर रही है। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कृषि उत्पाद भी बढ़ता है, परंतु गैर-फार्म सेक्टरों का उत्पाद अधिक तेज़ी से बढ़ता है। परिणामस्वरूप संवृद्धि पथ फार्म से गैर-फार्म सेक्टरों की ओर अंतरित हो जाता है। कृषि का अंश आर्थिक विकास में वृद्धि से क्यों घटता है? इसे समझने के लिए हमें माँग और आपूर्ति दोनों पक्षों को देखना चाहिए जो कृषि उत्पाद वृद्धि का निर्धारण करते हैं। एंजल के नियम के अनुसार, मांग की उच्च आय नम्यता के कारण खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति माँग घटती है और गैर-कृषि सेक्टर के माल/सेवाओं के लिए माँग बढ़ती है। परंतु व्यापार उदारीकरण और उच्च आय लोच बागवानी और डेयरी उत्पादों के लिए कृषि विविधीकरण का कृषि जिन्सों की माँग पर एंजल के नियम के प्रतिकूल प्रभाव को धीमा कर सकता है। इसलिए बागवानी और पशुधन सेक्टर की नीतिगत सहायता कृषि में विविधता लाने में सहायक है, इससे फार्म आय में वृद्धि हो सकती है। आपूर्ति पक्ष से कृषि प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी, मानव और अन्य कारकों के कारण ह्रासमान प्रति लाभ के नियम के अधीन होता है। भारत में अधिकांश वस्तुओं के मामले में कृषि उत्पादिताएँ या तो हाल के वर्षों में घटी हैं या अवरुद्ध रही हैं। मृदा, उर्वरता का ह्रास, अनुसंधान और विस्तार में कम निवेश, भौम जल संसाधनों की क्षीणता, कृषि का अति रासायनीकरण, निम्न मानव पूँजी आधार, उभरते हुए क्षेत्रों जैसे बागवानी और डेयरी सेक्टरों को कम नीतिगत सहायता और मुख्यतया

कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्यों के लिए प्रवर्तन के कारण निवल कृणित, क्षेत्रफल (NSA) में ह्रास भारत में कम कृषि वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

7.4.2 रोज़गार में योगदान

कृषि न केवल अधिकांश ग्रामीण श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोज़गार देती है बल्कि ग्राम गैर-फार्म सेक्टर में भी अप्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न करती है। यह रोजगार के इन अवसरों को फसल और पशुधन उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के माध्यम से पैदा होता है। कृषि प्रसंस्करण में शामिल है : (i) कृषि व्यापार कार्य; (ii) कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार, (iii) कृषि सूचना और संचार, (iv) पशु देखभाल और उपचार, (v) पादप संरक्षण आदि। 1951 में कुल श्रमिक बल का 69.5 प्रतिशत कृषि में था। यह प्रतिशत 1991 में भी 69.5 प्रतिशत था परंतु 2004-05 तक यह प्रतिशत घटकर 50 प्रतिशत हो गया। इस प्रवृति का क्या अभिप्राय है? इसका आशय है कि कृषि के समग्र रोज़गार अंश में गिरावट 1951-91 के चार दशकों की अवधि में केवल 2.6 प्रतिशत थी। परंतु यह 1991-2005 के उदारीकरण के बाद के वर्षों में सीधे 16.9 प्रतिशत गिरा। सैद्धांतिक अभिधारणा के अनुसार बाजार सुधारों ने रोज़गार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति की है। इससे श्रमिक बल कम उत्पादनकारी कृषि सेक्टर से उच्च उत्पादक गैर-कृषि क्षेत्र जा सका है। यह कुछ दशाब्दियों की अवधि में ''संरचनात्मक परिवर्तन'' प्राप्त हो पाया है जिसने अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर पर अत्यधिक निर्भरता में काफी कमी की है। किंतु संवृद्धि प्रक्रिया के समावेशी नहीं होने की दशा की यहाँ किसी न किसी सीमा तक विषाद आधारित पलायन भी हो सकता है या गरीब समर्थक नहीं थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 2003 के सर्वेक्षण बताते है कि देश में 50 प्रतिशत से अधिक परिवार ऋणग्रस्त हैं उन्होंने खेती के लिए पूँजी/चालू व्यय वहन के लिए ऋण लिया है। आप इस विषय पर इस पाठ्यक्रम की इकाई 26 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। ये मुद्दे हैं : पहला, कृषि श्रमिकशक्ति का गैर-कृषि सेक्टर में अंतरण और दूसरा, कृषि में कार्य दशाओं में सुधार।

बोध प्रश्न 2

नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए।

1) वे बाहरी आदान क्या हैं, जिन पर परिपक्व होती हुई कृषि निर्भर करती है?

.....

.....

.....

.....

2) उद्योग-कृषि संबद्धता किस प्रकार कृषिक या ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करती है?

.....

.....

.....

.....

3) विकास में वृद्धि से GDP में कृषि के शेयर में गिरावट क्यों होती है? इसके मांग/आपूर्ति दोनों पक्षों से उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

4) पिछले कुछ दशकों के दौरान किस अवधि में भारत में कुल रोज़गार में कृषि श्रमिक बल के अनुपात में अधिक गिरावट हुई है? इस तीव्र ह्रास का क्या कारण है?

.....

.....

.....

.....

7.4.3 निर्यात में योगदान

कृषि सेक्टर भारत की निर्यात आय का प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। बहुत समय तक कृषि आधारित उत्पाद, जैसे चाय, कॉफी, कपास और जूट, टेक्सटाइल, गर्म मसाले, तम्बाकू, काजू, चीनी आदि का अंश देश की कुल निर्यात आय के 50 प्रतिशत से अधिक रहा है। परंतु यह अंश आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के साथ-साथ घटा है। कृषि निर्यात का शेयर 1991-92 में 17.8 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 10.3 प्रतिशत हो गया। कृषि आयात का शेयर भी 1998-99 में 8.2 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 2.7 प्रतिशत पर आ गया। परंतु कुल व्यापार में कृषि व्यापार की मात्रा के गिरते शेयर का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यापार की मात्रा भी घटी है। वास्तव में, कृषि आयात की वार्षिक वृद्धि दर 20 प्रतिशत दर्ज हुई थी। जबकि कृषि निर्यात उपयुक्त अवधि के दौरान 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इससे प्रकट होता है कि सुधार के बाद की अवधि के दौरान कृषि निर्यात की अपेक्षा कृषि आयात अधिक तेज़ी से बढ़ा है। इससे समुचित नीति पहलुओं द्वारा निर्यात सुदृढ़ करने के उपाय करने की आवश्यकता सिद्ध होती है।

7.4.4 गरीबी न्यूनीकरण में भूमिका

जैसा कि हम अब अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबों की बहुत बड़ी संख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि सेक्टर में संवृद्धि बुनियादी ग्रामीण गैर-कृषि (कृषीतर) मज़दूरी उत्पादों और सेवाओं के लिए माँग बढ़ाती है। इनमें से अधिकांश माल स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जाता है तथा उपयोग किया जाता है। कृषि में उच्च वृद्धि से ग्रामीण गैर-फार्म सेक्टर में रोज़गार पैदा करने तथा आय बढ़ाने की बड़ी संभावना होती है। विश्व विकास रिपोर्ट (WDR-2008) ने तर्क दिया है कि कृषि वृद्धि गरीबी और असमानता घटाने में कृषीतर सेक्टरों में वृद्धि की तुलना में, चार गुणा प्रभावकारी है। ''सस्टेनिंगग्रोथ एंड शेयरिंग प्रोस्पेरिटी ''(ESCAP-2008) नाम

की एक अन्य यू.एन. रिपोर्ट भी कहती है कि एशिया प्रशान्त क्षेत्र में लगातार गरीबी दशाब्दियों से कृषि की उपेक्षा का परिणाम है। सर्वेक्षण कहता है कि क्षेत्र के गरीबों (अर्थात् लगभग 218 मिलियन) में हर तीसरे व्यक्ति को गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है यदि औसत कृषि श्रम उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसलिए कृषि आय में वृद्धि को गरीबी न्यूनीकरण में अधिक प्रभावकारी माना गया है। आप नोट कर सकते हैं कि भारत में गरीबी में गिरावट की दर 1990 के निम्न कृषि वृद्धि अवधि के दौरान की अपेक्षा 1980 की दशाब्दी की अपेक्षाकृत उच्चतर कृषि वृद्धि अवधि के दौरान के दशक अधिक थी। उदाहरण के लिए, भारत में ग्रामीण गरीबी 1993-94 और 2004-05 के बीच 9 प्रतिशत बिंदु तक गिरी, जबकि 1977-78 और 1987-88 के बीच यह 14 प्रतिशत बिंदु तक गिरी थी।

गरीबी, भूख और कुपोषण के मुख्य कारणों में से एक खाद्य सामग्री की अपर्याप्त सुलभता जो ग्रामीण भारत में व्यापक रूप में फैले हुए कुपोषण और भूख का मुख्य कारण है। इनसे ग्रस्त कामगार अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त कमाने के लिए शारीरिक रूप में बहुत अक्षम होता है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, गरीबी न्यूनीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह कार्य कृषि मज़दूरी बढ़ाकर और गरीब परिवारों को वहन करने योग्य मूल्य पर खाद्य और अन्य कृषि वस्तुओं को सुलभ बनाकर किया जा सकता है। परंतु गरीबी कम करने में कृषि संवृद्धि अधिक प्रभावी हो सकती है (यदि मानव विकास घटकों, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में पर्याप्त निवेश किया जाए)। बुनियादी शिक्षा का प्रावधान और कुशलता विकसित तथा उन्नयन करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण फार्म कामगारों के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पर्याप्त ज्ञान और कुशलताओं से वे नई प्रौद्योगिकी, बाजार के अवसरों और जोखिमों की अनुक्रिया करने के लिए अधिक सक्षम हो सकते हैं।

7.4.5 खाद्य और पौषणिक सुरक्षा में भूमिका

कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार (देखिए शब्दावली) दो तरीकों से खाद्य सुरक्षा की समस्या आसान करने में सहायता करता है : (i) उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पाद उपलब्ध कर, और (ii) फार्म और गैर-फार्म कार्यों में ग्रामीण श्रमिक बल के लिए अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा कर। राष्ट्रीय सुरक्षा की तुलना में खाद्य सुरक्षा कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारत खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए खाद्यान्न के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। यदि भारत खाद्यान्न के थोक आयातक/ खरीददार के रूप में विश्व बाजार में प्रवेश करता है तो खाद्य मदों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक सीमा तक बढ़ सकती हैं। इस प्रकार न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है बल्कि अन्य गरीब देशों को भी जोखिम में डाल सकती है। इसलिए संदेश यही है कि देश में लोगों की खाद्य और पौषणिक सुरक्षा का मुद्दा घरेलू कृषि में उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाए बिना प्रभावी ढंग से हल नहीं हो सकता।

7.4.6 समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने में योगदान

समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि विकास सबसे अधिक उत्कृष्ट है। श्रम प्रधान होने के कारण कृषि संवृद्धि निम्न प्रवेश बाधाओं (low entry barrier) से अतिरिक्त रोज़गार पैदा करता है। बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में गरीबों के लिए खाद्य कीमतें भी घटाती है जो अपनी अधिकांश आय खाद्य पर व्यय

करते हैं। तीव्र और समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार ने 11वीं योजना में कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया। 12वीं योजना का दृष्टिकोण प्रलेख भी संवृद्धि प्रक्रिया समावेशी बनाने के लिए कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने की संकल्पना करता है। इसके अलावा, कृषि और कृषीतर सेक्टरों के बीच संबद्धता का अभिप्राय है कि कृषि संवृद्धि में बढ़ोत्तरी बहुगुणक प्रभाव से अधिशेष उत्पन्न करती है। फार्म सेक्टर में उत्पन्न की गई अतिरिक्त आय भी गैर-फार्म सेक्टरों द्वारा अधिकांशतः स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुएं और सेवाएँ खरीदने पर व्यय की जाती है। गैर-फार्म सेक्टर में आय और रोज़गार की वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विविधता को प्रोत्साहित करती है। इस प्रक्रिया में फार्म और गैर-फार्म, दोनों सेक्टरों में वास्तविक मज़दूरी बढ़ती है। जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक निवेश करना संभव होता है। बेहतर शिक्षा और कौशल से कामगारों की भावी पीढ़ी उभरती हुई ग्रामीण गैर-फार्म कार्यों में विविधता ला सकती है। इसके अलावा, बेहतर शिक्षा और कौशल श्रमिक बल को गांव से शहरों में प्रवासन के लिए ''आकर्षण कारक'' के रूप में कार्य करता है जिसके कारण कृषि में श्रमिकों की कमी उत्पन्न होती है। परिणामतः किसान समुदाय श्रमिक बचत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार कृषि में निरंतर और टिकाऊ वृद्धि कालांतर में भारत जैसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि प्रक्रिया में समावेशिता लाती है जहाँ श्रमिक बल का बहुत बड़ा भाग अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करता है। जैसा कि पहले कहा गया है, कालांतर में इसका परिणाम श्रमिक बल का 'संरचनात्मक परिवर्तन' हो सकता है जिसमें कृषि पर अत्यधिक निर्भरता अधिक वांछित स्तर तक नीचे आ जाएगी।

7.4.7 आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा-जाल में भूमिका

कृषि आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान कामगारों को सुरक्षा नेट प्रदान कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, हाल ही के विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान बहुत से कामगारों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। यह देखा गया है कि बहुत से ग्रामीण प्रवासी कामगार जो ऐसे समय में बेरोजगार होते हैं अस्थायी रूप से अपने गांवों में वापस चले जाते हैं। ऐसे कामगारों को कृषि कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि वे अपने परिवारों से भोजन और आश्रय के रूप में सहायता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कृषि संकट के समय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सहायता करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हाल के विश्वव्यापी संकट से बचे रहने के कारणों में हमारा कृषि सेक्टर संकट से प्रायः अप्रभावित रहा है।

7.4.8 ऊर्जा सुरक्षा में भूमिका

कृषि को काफी पिछले समय से ऊर्जा का प्रमुख वैकल्पिक स्रोत माना जा रहा है। कृषि जैव पदार्थों को बायो गैस और बायो ईंधन पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। कई देशों ने भूसे और गन्ने से एथनॉल उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं 2003 और 2007 के बीच मकई उत्पादन में विश्व में हुई वृद्धि का दो-तिहाई भाग बायो ईंधन के उत्पादन में काम आया है।

संयुक्त राज्य अमरीका में मकई उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत एथानॉल पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। विश्व बाजार में तेल की ऊँची कीमतों ने बहुत देशों को जैव ईंधन का विकास करने की नीतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया

है। यह अनुमान लगाया गया है कि मकई का जैव ईंधन में परिवर्तन 50 डालर प्रति बैरल की तेल कीमतों पर लाभप्रद हो सकता है। ब्रजील विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पाद होने के कारण एथानॉल ईंधन का सबसे बड़ा प्रयोक्ता भी है। भारत में भी सरकार ने जेट्रोफा से जैव ईंधन और सीरे से एथानॉल उत्पादन करने के उपाय आरंभ किए हैं। विश्व भर में बहुत देशों में एथानॉल को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि परिवहन सेक्टर पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल का सम्मिश्रण करता है तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 800 मिलियन लीटर बचाने की क्षमता है भारत के चीनी उद्योग की गन्ना खोई (छिलका/मूसी) से 5000 मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है।

7.4.9 पारितंत्र सेवाओं में योगदान

कृषि विभिन्न प्रकार की सामग्री-इतर पारितंत्र सेवाएं भी प्रदान करती है, जैसे सामाजिक और कृषि वानिकी, जैव विविधता द्वारा मनोविनोद, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण अवशोषण आदि। कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कृषि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बाह्यताएँ उत्पन्न कर सकती है। एक ओर, यह आदान सघनता और रासायनीकरण के माध्यम से मृदा और जलस्रोतों को प्रदूषित करता है। दूसरी ओर, यह सकारात्मक बाह्यता भी उत्पन्न कर सकता है जैसे वन्य जीव, आर्द्र भूमि सेवाएँ, जैव पदार्थ आदि। जैव लैबल अधिक सुस्थापित पारितंत्र लैबलों में एक है। जैव खेती, जीव कीट नियंत्रण और मृदा तथा जल संसाधनों संरक्षण सहित सामग्री इतर पारितंत्र सेवाएं प्रदान करती है। परंतु किसान इस समय पारितंत्र सेवाओं के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। इसके लिए भी राष्ट्रीय लेखाकरण पद्धतियों में परिवर्तन कर उपयुक्त प्रोत्साहन/पुरस्कार निश्चित करना आवश्यक है।

7.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की बदलती हुई भूमिका

नव-उदारवादी नीति की शासन व्यवस्था के पिछले दो दशकों के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसके फलस्वरूप संवृद्धि पथ कृषि से गैर-कृषि सेक्टर की ओर अंतरित हुआ है। अब अर्थव्यवस्था को कृषि संवृद्धि में उतार-चढ़ाव से पृथक कर लिया गया है क्योंकि आज कृषि का GDP में योगदान 15 प्रतिशत से भी कम है। परंतु गैर-फार्म सेक्टर में आय बढ़ने, बढ़ते हुए शहरीकरण, काम धंधों के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता, आदि से कृषि उत्पादों की मांग का संयोजन महत्त्वपूर्ण तरीके से बदला है। हरित क्रांति अवधि के दौरान काफी सीमा तक कृषि विकास आपूर्ति चालित था और नीतिगत बल मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने पर था। आज कृषि विकास माँग चालित कारकों पर अधिक निर्भर है, (यद्यपि आपूर्ति पक्ष के कारक भी अभी प्रासंगिक है)।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण और प्रयोज्य आय में (विशेषकर मध्यम और उच्च वर्ग के परिवारों में) तीव्र वृद्धि से भारतीय उपभोक्ता कृषि उत्पादों में गुणवत्ता, विविधता, सुविधा और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन, भंडारण एवं मूल्य वृद्धि की गतिविधियों में कृषि व्यापारिक कंपनियों की सहभागिता बढ़ गई है। इस प्रकार भूमंडलीकरण, एकीकृत उपयोग श्रृंखला, द्रुत प्रौद्योगिकी नवीनताओं, पर्यावरण आदि मुद्दों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बदल दी है। इससे आधुनिक कृषि व्यापार के आधार पर कृषि में विविधताएँ लाने के

लिए इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक हो गया है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि, कृषि उत्पादों का इन विधियों से उपयोग भी बढ़ेगा : (i) कृषि उत्पाद का अपव्यय घटाकर; (ii) कृषि उत्पादों, विशेषकर नष्ट होने वाले उत्पादों, जैसे फल, सब्जियाँ और पशुधन उत्पाद की भंडारण अवधि सुधारकर। कई कृषि व्यापारिक कंपनियों ने पहले ही ये कार्य आरंभ भी कर दिये हैं: संविदा खेती, किसानों को प्रौद्योगिकी, आदान और विस्तार सेवाएँ प्रदान करना, पूर्व निर्धारित कीमतों पर उनका उत्पाद खरीदना, तथा इसके द्वारा किसानों के जोखिम न्यूनतम करना और बिचौलियों के बहुत से स्तरों को समाप्त करना। इस प्रकार, अन्य क्षेत्रों में {जैसे– (i) कृषि की आधारभूत संरचना का विस्तार करना, (ii) कृषि शिक्षा अनुसंधान और विकास, विस्तार, आदि (iii) बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार, विपणन, भंडारण सुविधाएँ आदि, (iv) निवेश प्रदाता, फार्म आपूर्तिकर्ता संयोजक, प्रोसेसर, थोक विक्रेता, दलाल, आयातक, निर्यातक, खुदरा व्यापारी, वितरक आदि; और (v) वायदा बाजार, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन।} सुविधाएँ सुधार कर कृषि की उभरती हुई संभावनाओं पर विचार करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की नवीकृत भूमिका का बहुत विराट चित्र उभरता है। ये सभी कृषि व्यापार कार्य पूरी तरह से प्राथमिक कृषि उत्पादन पर निर्भर हैं। तेज़ी से बढ़ते हुए कृषि व्यापारिक कार्यों के लिए प्राथमिक कृषि के महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती।

बोध प्रश्न 3

1) बताइये निम्नलिलिखत कथन सही हैं या गलत–

   क) पूर्ववर्ती विकास अर्थशास्त्रियों ने कृषि को औद्योगिक विकास के कारण संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा था।

   (सही / गलत)

   ख) GDP में कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में वृद्धि के साथ-साथ धीरे-धीरे घट रहा है।

   (सही / गलत)

   ग) अधिक व्यापक दृष्टि में कृषि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि उत्पादन और कृषि खाद्य व्यवस्था भी शामिल है।

   (सही / गलत)

   घ) 1990 के दशक की निम्न कृषि वृद्धि की अवधि की अपेक्षा 1980 की दशक की अपेक्षाकृत उच्चतर कृषि वृद्धि की अवधि के दौरान भारत में गरीबी न्यूनीकरण की दर उच्चतर रही।

   (सही / गलत)

   ङ) भारत खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए खाद्यान्न के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता।

   (सही / गलत)

च) हाल ही के वैश्विक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था के बचाव में कृषि का इस संकट से अप्रभावित रहना था।

(सही / गलत)

छ) विश्व बाजार में तेल की ऊँची कीमतों से जैव ईंधन के विकास की नीतियाँ बनाने के लिए बहुत देशों प्रोत्साहित हुए हैं।

(सही / गलत)

2) रिक्त स्थान भरिए :–

क) 1991-92 से भारत का कृषि निर्यात, कृषि आयात की अपेक्षा ..... बढ़ा।

ख) कुल विदेशी व्यापार में कृषि व्यापार का प्रतिशत अंश कालांतर में .... है।

ग) उत्पादन प्रक्रिया में कृषि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ..... उत्पन्न कर सकती है।

3) वे भिन्न-भिन्न क्षेत्र क्या हैं जिनमें ''उद्‌भावी कृषि'' की अधिकतम संभावना प्राप्त करने के लिए संकेंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है?

.....

.....

.....

.....

7.6 रोजगार / GDP अंतरण और रोज़गार नम्यता

चित्र 7.1 कुल GDP (1999-2000 कीमतों पर 2003-04 तक और उसके बाद 2004-05 की कीमतों पर) में कृषि और संबद्ध सेक्टर के GDP अंश शेयर की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि कृषि और संबद्ध कार्यों का योगदान पिछले 50 वर्षों के दौरान लगातार घटा है। यह 1960-61 में 50.6 प्रतिशत से 1970-71 में 44.3 प्रतिशत और आगे 1980-81 में 37.9 प्रतिशत हो गया था। GDP में कृषि का ये अंश 1990-91 में 31.4 प्रतिशत तक 2000-01 में 23.94 प्रतिशत और 2010-11 में केवल 14.2 प्रतिशत पाया गया। कृषि के इस अंश में आर्थिक सुधार की पिछली दो दशाब्दियों में अधिक तीव्र गिरावट आई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों में कृषि की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि हुई है। यद्यपि GDP में कृषि का अंश घटा है, परंतु कृषि उत्पादन का मान (करोड़ रुपये में व्यक्त) 1960-61 में 0.3 मिलियन से 2003-04 में 2.2 मिलियन (1999-00 की कीमतों पर) और 2004-05 में 3.0 मिलियन से 2010-11 में 4.9 मिलियन (2004-05 की कीमत) हो गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कृषि क्षेत्र में वास्तविक आय सारी अवधि के दौरान बढ़ी है, यद्यपि आय वृद्धि कृषीतर सेक्टरों की अपेक्षा कम रही है।

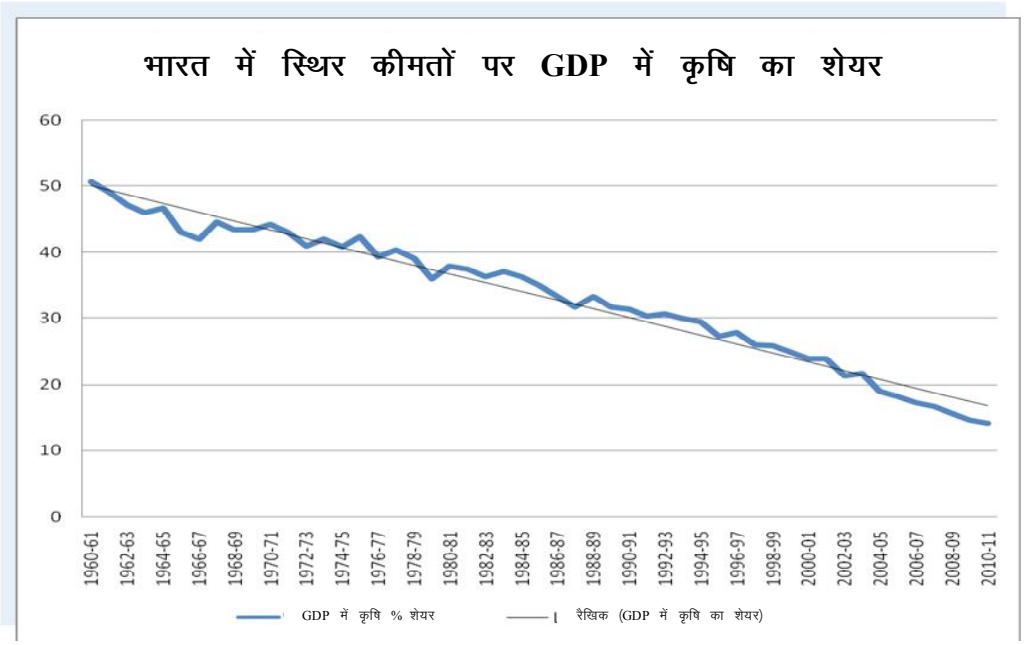

चित्र 7.1 : कृषि GDP में प्रवृत्ति (1961-2011)

राष्ट्रीय कृषीतर असंगित सेक्टर उपक्रम आयोग ने अनुमान लगाया है कि कृषि में ''प्रति कामगार GDP' (''श्रम उत्पादिता'' है) औद्योगिक सेक्टर GDP की लगभग एक-चौथाई और सेवा सेक्टर GDP की उत्पादिता का छटा भाग थी। वास्तव में कृषीतर सेक्टर से कृषि में श्रम उत्पादकता अनुपात 1983 से लगातर घट रहा है। इसका आशय है कि कृषि श्रम शक्ति की दशा इस अवधि के दौरान बिगड़ी है। इसके अलावा, कृषीतर कार्यों में अधिक मूल्य में रोज़गार तक किसानों/कृषि श्रमिकों की सीमित पहुँच के कारण भी वे अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहे हैं।

कृषि बनाम गैर-कृषि में रोजगार नम्यता

1993-94 से 2004-05 की अवधि की कृषि और कृषीतर सेक्टरों में रोज़गार वृद्धि तालिका 7.1 में प्रस्तुत की गई है। 1993-94 और 1999-00 के बीच कृषि रोज़गार में 0.03 प्रतिशत की नगण्य वृद्धि देखी गई (अर्थात् वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि) जबकि इसी अवधि के दौरान कृषि GDP 2.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ी थी। परिणामस्वरूप रोज़गार नम्यता 0.01 पर थी। (रोजगार वृद्धि का तद्नुरूपी GDP वृद्धि से अनुपात के रूप में परिभाषित, जो सेक्टर में उत्पन्न की गई या जोड़ी गई आय की प्रत्येक इकाई के लिए उत्पन्न किया गया रोजगार बताता है।) परंतु कृषीतर कार्यों में रोज़गार वृद्धि 2.5 प्रतिशत से अधिक थी और फलस्वरूप रोज़गार नम्यता भी 0.31 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। गैर-कृषि सेक्टर (5.03) में वास्तविक मज़दूरी की वृद्धि दर कृषि सेक्टर (2.74) की तुलना में लगभग दुगुनी थी। अगले पाँच वर्षों में कृषि सेक्टर की स्थिति में कुछ सुधार रहा। कृषीतर क्षेत्र में रोजगार नम्यता कृषि में 0.49 की तुलना में 0.65 था। परंतु कृषि क्षेत्र में रोजगार नम्यता में सुधार 1994-95 में 0.01 से 2000-2005 में 0.49 महत्त्वपूर्ण है। विशेष रूप से कृषि में भी वास्तविक मज़दूरी कृषीतर की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ी, अर्थात् पश्चोक्त की 0.13 की तुलना में यह पूर्वोक्त में 1.46 थी। ये तथ्य भारत में कृषि विकास की दृष्टि से स्पष्टतः उत्साहजनक हैं।

तालिका 7.1 : कृषि और कृषीतर सेक्टर में रोज़गार वृद्धि दर में प्रवृत्तियाँ

	कृषि			कृषीतर		
	1993-94 से 1999-00	1999-00 से 2004-04	1993-94 से 2004-05	1993-94 से 1999-00	1999-00 से 2004-04	1993-94 से 2004-05
रोज़गार	0.03	0.85	0.40.	2.53	4.66	3.49
GDP	2.88	1.76	2.37	8.11	7.22	7.71
रोज़गार नम्यता	0.05	0.49	0.17	0.31	0.65	0.45
वास्तविक मज़दूरी	2.74	1.46	2.15	5.03	0.13	2.77

स्रोत : असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों का राष्ट्रीय आयोग (NCEUS), भारत सरकार, 2009

बोध प्रश्न 4

1) रिक्त स्थान भरिये।

क) कुल GDP में कृषि का अंश 1960-61 में 50.6 प्रतिशत से घटकर 2010-11 ..... हुआ।

ख) कृषि क्षेत्र में वास्तविक आय 1961-2001 की अवधि के दौरान बढ़ी है, किंतु आय वृद्धि कृषीतर सेक्टरों की अपेक्षा ..... रही है।

ग) NCEUS अनुमानों के अनुसार कृषि में प्रति कामगार GDP 2004-05 में . ..... लगभग एक-चौथाई थी।

घ) 1993-94 और 2004-05 के बीच रोज़गार नम्यता ..... की अपेक्षा ..... में उच्चतर थी।

7.7 सारांश

आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका विकास अर्थशास्त्र के मुख्य सरोकारों में एक रहा है। इस विषय पर पिछले अधिकांश अध्ययन मूलतः परंपरागत कृषि सेक्टर से आधुनिक औद्योगिक सेक्टर में कारक संसाधनों के अंतरण द्वारा अर्थव्यवस्थाओं के संरचनात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया पर संकेंद्रित रहे हैं। कृषि की भूमिका मुख्यतया खाद्य सामग्री मुहैया करने, काम पैदा करने, निर्यात आय अर्जन करने, निवेश के लिए बचत करने, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्राथमिक माल का उत्पादन करने तक सीमित थी। परंतु कृषि की समकालीन भूमिका इस प्रत्यक्ष बाजार समामेलित योगदान से भी आगे निकल जाती है। अब कृषि वे अप्रत्यक्ष गैर-सामग्री योगदान प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सार्वजनिक पदार्थ, सामाजिक सेवा लाभ और पर्यावरण सेवाएं हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जल संसाधन, जैव विविधता, ग्रामीण गरीबी, खाद्य ईंधन और आजीविका सुरक्षा आदि ने कृषि को एक बार फिर विकासशील देश की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समग्र विकास एजेंडा में रख दिया है।

7.8 शब्दावली

GDP : सकल घरेलू उत्पाद–राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत (संसाधनों के स्वामित्व को ध्यान में रखे बिना) किसी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पादन।

संबद्धता : उत्पाद के प्रवाह क्रम में विभिन्न क्षेत्रकों के बीच परस्पर निर्भरता।

श्रम का सीमांत उत्पाद : अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए श्रम के प्रयोग में एक इकाई परिवर्तन के कारण कुल उत्पाद में निवल परिवर्तन।

गैर-कृषि सेक्टर : इसमें कृषि और संबद्ध कार्यों के अलावा सभी आर्थिक कार्य शामिल हैं।

CSO : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन – राष्ट्रीय लेखा आंकड़े जैसे, GDP, सकल घरेलू उत्पाद बचत आदि के आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है।

संरचनात्मक परिवर्तन : सेक्टर अनुसार कामगारों के वितरण आदि में जो विकास की अवधि में आये बड़े परिवर्तन। इस समय नीति निर्धारकों के समक्ष कृषि में भी अन्य क्षेत्रकों की भांति श्रम की उच्च उत्पादिता प्राप्त करते हुए इस क्षेत्र में व्यस्त जनसंख्या (वर्तमान स्तर 50 प्रतिशत है) के अनुपात में यथेष्ठ कमी लाना है। यह ''समावेशी संवृद्धि'' के सरोकारों को लेकर चिंता का भी समाधान होगा।

श्रम उत्पादकता : इसे रुपयों में व्यक्त किया जाता है और सेक्टर की आय को सेक्टर में नियुक्त कामगारों की कुल संख्या द्वारा भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यह सेक्टर में प्रति व्यक्ति औसत आय निरुपित करता है।

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Valdes A and Foster W (2010): Reflections on the Role of Agriculture in Pro-Poor Growth, World Development Vol. 38, No. 10, pp. 1362–1374, 2010.

Johnston, B. F., & Mellor, J. (1961): The role of agriculture in economic development. American Economic Review, 51(4), 566–593.

Lewis, A. (1955): *The Theory of Economic Growth*, R.D. Irwin. Homewood, Illinois.

Luc Christiaensen, Lionel Demery, Jesper Kuhl (2011): The (Evolving) Role of Agriculture in Poverty Reduction—An Empirical Perspective, Journal of Development Economics, Vol. 96, (2011), 239-254.

Schultz, T. W. (1964): *Transforming Traditional Agriculture*. Yale: Yale University Press.

Singh S.P. (2010): Agriculture under Neoliberal Policy Regime, in *Alternative Economic Survey, India: Two decades of Neoliberalism*, Dannis Books.

World Bank (2008): *World Development Report: Agriculture for Development*, The World Bank, Washington D.C.

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 7.1 देखिए और उत्तर दीजिए।

2) भाग 7.2 देखिए और उत्तर दीजिए।

3) भाग 7.2 देखिए और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) भाग 7.3 का पहला और दूसरा पैरा देखिए और उत्तर दीजिए।

2) भाग 7.3 का अंतिम पैरा देखिए और उत्तर दीजिए।

3) उपभाग 7.4.1 देखिए और उत्तर दीजिए।

4) उपभाग 7.4.2 देखिए और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) क) सही

   ख) सही

   ग) भाग 7.4 देखिए और उत्तर दीजिए।

   घ) सही

   ङ) सही

   च) सही

   छ) सही

2) (क) मंद, (ख) घटा (ग) बाह्यताएँ

3) भाग 7.5 के दूसरे पैरा का अंतिम भाग देखिए और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 4

1) भाग 7.6 देखिए और उत्तर दीजिए।

2) भाग 7.6 देखिए और उत्तर दीजिए।

3) भाग 7.1 देखिए और उत्तर दीजिए।

4) भाग 7.1 देखिए और उत्तर दीजिए।